

जाएगी। किन्तु प्रशासन ने अपने वायदे से मुकरते हुए इस सर्दी के मौसम में कजाखस्तान के करासाई जिले में स्थित 11 हिन्दू अल्पसंख्यकों के मकानों को ध्वस्त कर दिया।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह कजाखस्तान सरकार के इस कृत्य पर शीघ्र अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करे एवं भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो तथा पीड़ित परिवारों की सहायता एवं सुरक्षा के पुख्त इंतजाम हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाये।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति से वहाँ हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार को तो उक्त मामले में विशेष चिन्ता होनी चाहिए थी।

इसके पूर्व भी दुनिया के अनेक देशों में हिन्दुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से हिन्दुओं के मंदिरों को ढहाया गया था और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई गई थी।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करती हूँ।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे) : श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी अपने आपको इससे संबंध किया है। Her name is here.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात) : महोदय, मैं भी आने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

Demand for revision of royalty on coal

SHRI SURENDRA LATH (Orissa): Sir, I would like to bring to the notice of the Government the need for revision of royalty on coal. The 11th Finance Commission has recommended for the revision of royalty every three years and in case such revision does not take place, the States should be fully compensated in the shape of grant-in-aid.

The Planning Commission and also the 12th Finance Commission categorically recommended *ad-valorem* reason for royalty. The State

[1 December, 2006]

RAJYA SABHA

Governments in the Eastern Zonal Council meeting supported this proposal.

The Ministry of Coal constituted a Committee under the Chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Coal for the revision of rates of royalty. The Committee does not have any representative from the States, which have maximum of stake in the revision of coal royalty.

The coal royalty is supposed to be revised with effect from 16.8.2005. Due to delay in revision and discrimination in the rate of revision, the State Governments are sustaining heavy loss. I appeal to the Central Government to take immediate steps for revision of royalty and compensate the loss incurred by the States due to delay. Thank you.

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबद्ध करता हूँ।

श्री विजय कुमार रुपाणी (गुजरात) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबद्ध करता हूँ।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष से संबद्ध करता हूँ।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबद्ध करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): We shall now take up the next item.

GOVERNMENT BILL

The Central Institute of English and Foreign Languages University Bill, 2006

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATID. PURANDESWARI): Sir, I move:

"That the Bill to establish and incorporate a teaching University for promotion and development of English and other Foreign Languages and their Literature and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."